जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 171 दिनांक:04-06-2022 शनिवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

भारत में 84 दिन के बाद एक दिन में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,68,585 हो गई है।

घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश

देश में फिर बढ़ रहा कोरोना, एक दिन में मिले कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारत में 84 दिन के बाद एक दिन में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,68,585 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 21,177 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 4,041 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि दस मरीजों की मौत हो गई, जिससे संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,24,651 पर पहुंच गई।

आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 21,177 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05 प्रतिशत है। वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74 प्रतिशत है। गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार हो गए थे।

केदारनाथ व वैष्णों देवी के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराने वाले हो जाएं सावधान

नई दिल्ली (ईएमएस)। अगर आप भी हेलीकॉप्टर के जरिए वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने कथित तौर पर एक नकली हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग मॉडयूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के मास्टरमाइंड और वेबसाइट डेवलपर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (आईएफएसओ) केपीएस मल्होत्रा ने शुक्रवार को इस मॉडयूल का खुलासा करते हुए बताया कि यह सिंडिकेट भारत के विभिन्न हिस्सों यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, फिरोजाबाद आदि से काम कर रहा था। डीसीपी (आईएफएसओ) केपीएस मल्होत्रा ने शुक्रवार को इस मॉडयूल का खुलासा करते हुए बताया कि यह सिंडिकेट भारत के विभिन्न हिस्सों यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, फिरोजाबाद आदि से काम कर रहा था।

कश्मीर पर होगा बड़ा फैसला रॉ के चीफ एनएसए और एलजी संग जारी अमित शाह की मीटिंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई है। पहले राउंड की मीटिंग 2 बजे खत्म हुई है और एक बार फिर से 3 बजे मीटिंग शुरू होगी। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद हैं। उनके अलावा कई और बड़े अधिकारी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं पर हुई मीटिंग में रॉ के चीफ सामंत गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। बैठक के बाद कश्मीर घाटी में हिंदू अल्पसंख्यकों एवं सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई फैसला लिया जा सकता है। बीते 5 महीने में जम्मू कश्मीर में 16 हत्याएं आतंकवादी कर चुके हैं और उनसे निपटना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से अल्पसंख्यकों को उम्मीद है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी। इससे पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इसी सप्ताह फैसला लिया था कि हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ही पोस्टिंग मिलेगी। उन्हें जिला मुख्यालयों में ही तैनात किया जाएगा। लेकिन कुलगाम में बैंक के अंदर घुसकर प्रबंधक विजय कुमार की हत्या किए जाने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कश्मीर में किस स्थान पर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। विपक्षी दल भी कश्मीर में हत्याओं को लेकर केंद्र सरकार को घर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि सरकार फिल्म में बिजी थी और कश्मीर में इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं। यही नहीं असदुद्दीन ओवैसी भी इस मसले पर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इस बीच आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आखिर भाजपा और आरएसएस के लोग शांत क्यों हैं, जब कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन लोगों की रणनीति पूरी तरह से असफल रही है।

भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज देने को मंजूरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब पांच करोड़ अंशधारकों को वर्ष 2021-22 के लिये भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज देने को मंजूरी दे दी है. चार दशकों में यह ईपीएफ पर मिलने वाली सबसे कम ब्याज दर है. इस साल मार्च में ही ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2021-22 के लिये देय ब्याज दर को 2020-21 के 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का निर्णय किया था. शुक्रवार को जारी ईपीएफओ कार्यालय आदेश के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2021-22 के लिये ईपीएफओ अंशधारकों को 8.1 प्रतिशत ब्याज की मंजूरी मिलने के बारे में सूचना दी है.

श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिये वित्त मंत्रालय को भेजा था. सरकार से मंजूरी मिल जाने के बाद ईपीएफओ अब कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में ब्याज राशि डालना शुरू करेगा. ईपीएफ जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज 1977-78 के बाद सबसे कम है. उस समय ब्याज दर 8 प्रतिशत रही थी. सीबीटी में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी केई रघुनाथन ने कहा कि जिस गति से श्रम एवं वित्त मंत्रालयों ने ब्याज दर को मंजूरी दी है, कर्मचारियों को कोष की जरूरत को देखते हुए वह वास्तव में सराहनीय है. इससे उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

सीबीटी ने 2020-21 के लिये ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय मार्च 2021 में किया था. वित्त मंत्रालय ने इसे अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी. उसके बाद ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 2020-21 के लिये 8.5 प्रतिशत की दर से ईपीएफ खातों में ब्याज डालने का निर्देश दिया था. ईपीएफओ ने 2019-20 के लिये मार्च 2020 में भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर सात साल के निचले स्तर 8.5 प्रतिशत पर कर दिया था. इससे पहले, 2018-19 में यह 8.65 प्रतिशत था.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिये ईपीएफ ब्याज दर 2012-13 के बाद सबसे कम थी. उस समय इसे कम कर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया था. ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 2016-17 के लिये 8.65 प्रतिशत और 2017-18 के लिये 8.55 प्रतिशत ब्याज दिया था. इससे पहले, वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी. जबकि 2013-14 और 2014-15 में ब्याज दर 8.75 प्रतिशत थी. यह 2012-13 में दिये गये 8.5 प्रतिशत ब्याज से ज्यादा था. वित्त वर्ष 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज 8.25 प्रतिशत रखा गया था.

कांग्रेस ने पूछा, घाटी में शांति कायम करने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में लक्षित हत्या की घटनाओं को लेकर शुक्रवार को केंद्र पर तीखा प्रहार कर पूछा कि अब सरकार को 'दुष्प्रचार' की बजाय यह बताना चाहिए कि वह सामान्य स्थिति बहाल करने तथा हत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? पार्टी के नेता और सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि शांति बहाली के लिए सरकार को संबंधित पक्षों से बात कर जम्मू-कश्मीर की जनता और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।उन्होंने कहा, ''मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। मुझे इस बात का दुख है कि कश्मीर के मुद्दे का समाधान करने में कुशल राजनीतिक नेतृत्व की कमी दिखती है। यह जटिल मुद्दा है। अगर आपका संवेदनशील चेहरा होता है, समावेशी चेहरा होता है, तब चीजें नियंत्रण में आ जाती है।''

तन्खा ने कहा, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कश्मीर का मुद्दा अनुच्छेद 370 या किसी कानून से बड़ा है.. अगर आप को कश्मीर के मुद्दे का निदान करना है और अगर आप शांति चाहते हैं, तब आपको संबंधित पक्षों से बात करनी होगी। संबंधित पक्षों से बात किए बिना वहां शांति नहीं आ सकती। सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा।'' उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा,''जम्मू-कश्मीर में छह-सात साल से राज्यपाल शासन है। आठ साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब आप (सरकार) यह आरोप नहीं मढ़ सकते कि 60 साल में क्या हुआ? आपसे देश पूछना चाहता है कि आपने कश्मीर के लिए क्या ठोस कदम उठाए, कश्मीर को लेकर आपका श्वेत पत्र कहां है?'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री जी हर छोटी बात पर ट्वीट करते हैं। काश, प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर भी ट्वीट करते।''

तन्खा ने कहा, हम केंद्र से अपील करते हैं कि आप सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाइए और इस बारे में देश को बताइए। दूसरे दलों को विश्वास में लीजिए। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना दिखाइए।'' उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा दुष्प्रचार करने की बजाय ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, ''हत्याओं को रोकने के लिए जरूरी कदम 24 घंटे में उठाए जाने चाहिए। यह पूछने पर कि वह जिन संबंधित पक्षों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, क्या उनमें अलगाववादी भी शामिल हैं, तब तन्खा ने कहा, ''यह यहां चर्चा का विषय नहीं है। यह सरकार तय करेगी कि किससे बात करनी है।''

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा, सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या के पीछे उसका गिरोह

पुलिस सूत्रों ने दी यह जानकारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू (सिद्धू मूसेवाला) की निर्मम हत्या के पीछे उनका गिरोह जिम्मेदार था। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी। 28 वर्षीय मूसेवाला की 29 मई को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह एक कार में यात्रा कर रहे थे और लगभग एक दर्जन हमलावरों ने उन पर 30 से अधिक गोलियां चलाईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'मृत' घोषित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ठउसने कबूल किया कि उसका गिरोह हत्या (मूसेवाला की हत्या) के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह भी कहा कि वह सीधे तौर पर इसके पीछे नहीं था क्योंकि वह जेल में बंद है।ठ

वर्तमान में मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) मामले में तिहाड़ जेल में बंद, बिश्नोई कथित तौर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में उसके खिलाफ दर्ज पांच दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है। बिश्नोई ने एक बार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल हर एंगल से घटना की जांच कर मामले में बिश्नोई से भी पूछताछ कर रही है। यह भी पता चला है कि गैंगस्टर बिश्नोई पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्र ने कहा, वह घटना के बारे में ब्यौरा नहीं दे रहा है, लेकिन उसने कबूल किया है कि इस हत्या के पीछे उसका गिरोह था।ठ इस बीच, लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे सचिन बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने दावा किया था कि मूसेवाला की हत्या पिछले साल अगस्त में यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला था। सूत्रों ने बताया कि विक्की मिद्दुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था।

किसान अब डाक विभाग की मदद से अपने घर पर 'पीएम किसान सम्मान निधि' प्राप्त कर सकेंगे

लखनऊ (ईएमएस)। किसान अब डाक विभाग की मदद से अपने घर पर 'पीएम किसान सम्मान निधि' के रुपये प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली धनराशि को सुगमता से मुहैया कराने की पहल की है।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया, ' किसानों को किसान सम्मान निधि के रुपये निकालने के लिए बैंक शाखा या एटीएम में जाना पड़ता है और ग्रामीण इलाकों में यह दुरूह होता है। हम किसानों के लिए इसे सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ''

यादव ने बताया कि डाक विभाग पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए 'आपका बैंक, आपके द्वार' अभियान शुरू कर रहा है। उन्होंने बताया कि किसान अपने आधार से जुड़े बैंक खाते से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के साथ किसान सम्मान निधि के रुपसे घर बैठे निकाल सकते हैं। इसके लिए एक डाक प्रतिनिधि उनके घर आएगा।

अधिकारी ने बताया कि यह अभियान चार जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को सालाना तीन बार में 6000 रुपये मिलते हैं जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं।

कानपुर में थम नहीं रहा बवाल कई इलाकों में फिर पथराव

कानपुर (ईएमएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के बावजूद कानपुर में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रह-रहकर कई इलाकों में दंगाई पथराव कर रहे हैं। संकरी गलियों में नारेबाजी करते हुए उपद्रवी पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पथराव गलियों से रुक-रुककर हो रहा है। पुलिस जिधर जाती है उधर थम जाता है पथराव। जिधर से हटती है उधर से पथराव शुरू हो जाता है। उपद्रवियों को हावी होते देख पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पूरे साजो सामान के साथ गलियों में घुसकर उपद्रवियों को खदेड़ा जा रहा है। लाठीचार्ज के जरिए हालात को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। पत्थरबाजों की धरपकड़ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में हुए बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को जल्द हालात को काबू में करने को आदेश दिया है। सीएम ने आदेश दिया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा ना जाए।

'ई-संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जोड़ा गया

नई दिल्ली (ईएमएस)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने कहा कि सरकार की 'ई-संजीवनी' टेलीमेडिसिन सेवा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ जोड़ा गया है। एनएचए ने कहा कि इस कदम से ई-संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ता आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड (एबीएचए) बनाकर स्वास्थ्य संबंधी अपने मौजूदा रिकॉर्ड से उसे जोड़ सकते हैं। उपयोक्ता ई-संजीवनी की मदद से अपने स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड को चिकित्सकों के साथ साझा कर सकते हैं जिससे उन्हें काफी लाभ होगा।

दोनों सेवाओं को आपस में जोड़ने से होने वाले लाभ के बारे में एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ.आर.एस.शर्मा ने कहा, ''एबीडीएम का लक्ष्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरियों को कम करने और संबंधित पक्षों के लिए डिजिटल रास्ते तैयार करना है। उन्होंने कहा, ''ई-संजीवनी का एबीडीएम के साथ जोड़ना ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां एबीएचए के 22 करोड़ उपयोक्ता ई-संजीवनी की मदद से बने अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को चिकित्सकों के साथ साझा कर सकते और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ई-संजीवनी फिलहाल दो संस्करण में उपलब्ध है।

पहला संस्करण है... ई-संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)। यह चिकित्सक से चिकित्सक को जोड़ने वाली टेलीमेडिसिन सेवा है, इसके तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र पर चिकित्सक से मिलने आया लाभार्थी ऑनलाइन उन चिकित्सकों के साथ भी अपनी समस्या साझा कर सकता है जो किसी दूसरे स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। दूसरा संस्करण, ई-संजीवनी ओपीडी के तहत देशभर में मरीजों का उनके घरों से सीधे चिकित्सकों से संपर्क कराया जाता है। एनएचए ने एक बयान में कहा कि ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी और ई-संजीवनी ओपीडी दोनों को एबीडीएम के साथ जोड़ दिया गया है।

देश भर में चिंता के बीच केरल से कांग्रेस के लिए गुड न्यूज

नई दिल्ली (ईएमएस)। केरल की थ्रिक्काकारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में विपक्षी कांग्रेस-यूडीएफ ने जीत हासिल की। इस तरह राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी दल की उम्मीदवार उमा थॉमस ने वामपंथी उम्मीदवार जो जोसेफ को पच्चीस हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया। थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में माकपा ने जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व प्रचार किया था। माकपा ने हार को 'अप्रत्याशित' और 'स्तब्ध करने वाला' करार दिया। वहीं, कांग्रेस ने कहा कि उनकी शानदार जीत विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर चेहरे पर एक तमाचे जैसी है। पार्टी के प्रमुख नेता रहे दिवंगत पीटी थॉमस की पत्नी उमा ने शुरुआत से ही सभी 12 राउंड की मतगणना में प्रभावशाली बढ़त बनाए रखी। उन्होंने 72,000 से अधिक मत हासिल किए। वहीं, उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी जोसेफ को 47,000 से अधिक मत मिले। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी ए एन राधाकृष्णन तीसरे स्थान पर रहे। पिछले वर्ष थॉमस के निधन से रिक्त हुई थ्रिक्काकारा सीट पर उपचुनाव हुए थे। विजयन के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों और अधिकांश विधायकों, नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्र में कई सप्ताह तक व्यापक अभियान चलाया।

कार्टून कोना

चुनाव में सोशल मीडिया का उपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उम्र के अंतिम पड़ाव में सास को चैन से रहने दो...घर छोड़ दे बहू

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक अहम फैसले में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की याचिका पर उसकी बहू को अपनी सास का घर छोड़ने की नसीहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग महिला अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। ऐसे में उन्हें चैन से रहने की जरूरत हैं। हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में संतुलन बनाते हुए बहू के लिए एक अन्य घर की भी व्यवस्था दी। बुजुर्ग महिला मुंबई के विले पार्ले में रहती हैं। शीर्ष अदालत ने बहू को विले पार्ले वाले घर को छोड़ने के बाद लोनावाला के घर में शिफ्ट करने को कहा है। बुजुर्ग महिला, उनका बेटा और उनकी बहू, जस्टिस अजय रस्तोगी और बी वी नागरत्ना की वेकेशन बेंच के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। विधवा सास ने बहू पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बुजुर्ग महिला ने मुंबई में उसके विले पार्ले वेस्ट हाउस में चैन से रहने की गुहार लगाई। सास ने कहा कि बहू ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। वहीं, बहू ने कहा कि उसने शादी में 22 साल तक गंभीर यातना और उत्पीड़न सहा है।

बहू का कहना था कि उसे परेशान किया गया तो उसने सह लिया लेकिन जब ससुराल वालों ने उसके दो बेटों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो वह सह नहीं पाई। महिला के दो बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं। महिला अपने पति और सास के घर में ही अलग रहती है। बहू ने अपनी सास की तरफ से बेदखली की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह एक ही घर में अलग रहने की मौजूदा व्यवस्था जारी रख सकती है।

उसके पति ने कहा कि 2018 तक वैवाहिक जीवन सुचारू था जब अचानक उसके अजीब और हिंसक व्यवहार से सब कुछ उल्टा हो गया। अदालत ने पति को अपनी अलग हुई पत्नी के चरित्र पर आक्षेप लगाने से रोक दिया। बूढ़ी औरत, उसके बेटे और बहू को सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि बुजुर्ग महिला जीवन के अंतिम पड़ाव में शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। उन्हें कुछ मानसिक शांति मिलनी चाहिए लेकिन साथ ही, बहू के पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए। बेंच ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम और बहू के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है।

तुर्की ने रुबेला वायरस बताकर गेंहू भारत को लौटाया, उसी गेंहू को मिस्त्र भेज दिया

नई दिल्ली (ईएमएस)। तुर्की ने भारत का जो गेहूं खराब बता लौटा दिया था, अब गेहूं की उस खेप को मिस्त्र भेज दिया गया है। मिस्त्र ब्रेड की कमी से जूझ रहा है। गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्त्र, भारत सहित अन्य देशों से कम कीमत पर गेहूं खरीदना चाहता है।

सूत्रों ने बताया, तुर्की ने जिस गेहूं को गुणवत्ता खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया था, उस मिस्त्र भेज दिया गया है। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इससे पहले ही भारत ने तुर्की के लिए गेहूं की 56,000 टन की खेप को मंजूरी दे दी थी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि गेहूं की खेप को भारत से रवाना करने से पहले क्वारंटीन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था।

उन्होंने कहा कि गेहूं की खेप लेने से इनकार करने पर अभी तुर्की के अधिकारियों से बात नहीं हो सकी है। पांडेय ने कहा, गेहूं की यह खेप भारतीय कंपनी आईटीसी लिमिटेड की थी। मुझे बताया गया कि इस सौदे को लेकर वित्तीय लेनदेन पूरा हो गया था। भारतीय कंपनी ने यह गेहूं एक विदेशी कंपनी को बेचा था, जहां से यह गेहूं तुर्की की कंपनी के पास पहुंचा। तुर्की ने भारत के गेहूं में रुबेला वायरस की शिकायत की थी एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के गेहूं मे रुबेला वायरस पाए जाने की वजह से लौटा दिया गया था। आईटीसी के प्रवक्ता ने कहा, आईटीसी ने नीदरलैंड्स की एक कंपनी को यह गेहूं बेचा था। गेहूं की जांच और सभी तरह की मंजूरियों के बाद ही इस खेप को भेजा गया था। इस बारे में तुर्की और मिस्त्र के दूतावासों ने कोई जवाब नहीं दिया है। सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि पांच देशों ने गेहूं निर्यात पर बैन के बाद आधिकारिक रूप से भारत से गेहूं मांगा है। सरकार का कहना है कि अब से निजी कंपनियों को नहीं बल्कि सरकारों को ही गेहूं बेचा जाएगा।

घटनाक्रम से वाकिफ निर्यातकों का कहना है कि गेहूं की खेप लगभग दो हफ्ते में तुर्की पहुंची थी। हो सकता है कि इस दौरान तापमान में बदलाव और नमी से गेहूं खराब हो गया हो। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि गेहूं में वायरस होने की संभावना नहीं होगी। उन्होंने कहा, रुबेला वायरस बीज या मिट्टी में संक्रमण की वजह से होता है। जहाज में गेहूं लादे जाने से पहले इसका पता लगाया जा सकता था। यह लापरवाही का मामला हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने भारत के गेहूं में वायरस की लगातार मिल शिकायतों को लेकर चिंता जाहिर की है। इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया ने क्वालिटी का हवाला देकर भारत के कृषि उत्पादों को ठुकरा दिया था। एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की घटनाओं का देश की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। मंत्रालय को इस तरह के मामलों से निपटना चाहिए। इस तरह के मामले इसलिए पकड़ में नहीं आ पाते क्योंकि भारत में टेस्टिंग लैब सही तरीके से काम नहीं करते।

मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर महिला के शरीर से निकाले गए तीन करोड़ के मादक पदार्थ

मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर युगांडा की एक महिला को 49 कैप्सूल में 535 ग्राम हेरोइन और 15 कैप्सूल में 175 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि तीन करोड़ रुपये की कीमत के मादक पदार्थ महिला के शरीर में छिपाए गए थे। उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए महिला को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि युगांडा से मुंबई में एक संदिग्ध महिला के आने की विशेष सूचना के आधार पर 28 मई को चलाए गए एक अभियान के तहत उसे पकड़ा गया था।महिला का पता लगाने के बाद उसके सामान में जांच के दरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वह अपने शरीर में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रही थी। 'लगातार पूछताछ करने पर महिला ने स्वीकार किया कि विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले टेप के उपयोग से उसके शरीर में 11 कैप्सूल छिपाए गए थे। 110 ग्राम हेरोइन युक्त कम से कम 10 कैप्सूल हटा दिए गए थे और शेष की निकासी के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनसीबी अधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते के दौरान कुल 54 कैप्सूल निकाले गए।

महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की होने लगी मांग

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगी एनसीपी

मुंबई (ईएमएस)। बिहार में जारी चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। खबर है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की तैयारी कर रही है। इधर, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को सहमित मिल गई है। गुरुवार को राकंपा ने अलग-अलग समुदायों के सामाजिक स्तर का पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग उठाई। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि एनसीपी इस मुद्दे पर सीएम ठाकरे से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील करेगी। उन्होंने बताया कि शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित गणना को गुरुवार को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया और सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 23 फरवरी की समय सीमा निर्धारित की। मुख्यमंत्री कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपेक्षित अधिसूचना जारी होते ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जातियों के सर्वेक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल प्राधिकरण होगा तथा अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाएगी।

सुबहानी ने कहा कि यह कार्य फरवरी, 2023 तक पूर्ण होगा, जिसका नोडल विभाग होगा सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल पदाधिकारी सभी जिलों में जिला पदाधिकारी होंगे, जो इस कार्य के लिए ग्राम, पंचायत, अन्य सभी स्तरों पर भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मियों की सेवा ले सकेंगे। जाति आधारित गणना में आर्थिक गणना भी शामिल होगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता के एक दिन बाद ही मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है। केंद्र द्वारा एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति समूहों की गणना करने में असमर्थता व्यक्त करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह अभ्यास शुरू किया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा जातीय जनगणना के पक्ष में 2018 और 2019 में दो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए गए थे। नीतीश कुमार और मुख्य विपक्षी पार्टी राजद का तर्क रहा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों का एक नया अनुमान आवश्यक है क्योंकि पिछली जातीय जनगणना 1921 में हुई थी।

जन हितैषी

टमाटर का मीटर

टमाटर की महंगाई का मीटर लगातार ऊपर ही जा रहा है। कीमतें आसमान छू रहीं हैं। दिल्ली को छोड़कर, टमाटर की खुदरा कीमतें 77 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गईं हैं। सरकार का कहना है कि टमाटर की संभावित कम सप्लाई के चलते कीमत में तेजी आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक जून को कोलकाता में टमाटर का खुदरा मूल्य 30 अप्रैल के 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 77 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई में भी, खुदरा टमाटर की कीमत एक मई के 36 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर एक जून को 74 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि चेन्नई में यह कीमत 47 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 62 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, प्रमुख उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और विभिन्न शहरों में यह 50 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच चल रही है। व्यापारियों और विशेषज्ञों ने खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से सप्लाई की संभावित कमी को जिम्मेदार ठहराया है। कुल मिलाकर देश में महंगाई आसमान छू रही है। जहां एक ओर खुदरा महंगाई आठ साल के शिखर पर पहुंच गई है, जबकि थोक महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए शिखर पर पहुंच चुकी है। इसे काबू में करने के लिए पीएम मोदी लगातार कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनकी इस राह में टमाटर बड़ा रोड़ा बन सकता है। टमाटर के लगातार बढ़ते भाव अब सरकार के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्याज समेत अन्य सब्जियों का भारत की राजनीति में उथल-पुथल लाने कई बार अहम योगदान रहा है। सब्जियों का देश में सरकारों को गिराने का एक असामान्य इतिहास है और भारत में टमाटर की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, उसने राजनेताओं को परेशानी में डाल दिया है। बता दें कि टमाटर, आलू और प्याज ऐसी सब्जियां हैं जो कि हर रोज रसोई में इस्तेमाल होती हैं और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी सीधे रसोई के माध्यम से आम आदमी को प्रभावित करती हैं। खाद्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को देखें तो भारत में टमाटर का औसत खुदरा मूल्य एक महीने पहले 70 फीसदी और एक साल पहले की तुलना में 168 फीसदी तक बढ़कर मंगलवार तक 53.75 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। भारत में खाना पकाने के तेल से लेकर गेहूं के आटे तक हर चीज की कीमतें चढ़ गई हैं, जिससे अप्रैल में मुद्रास्फीति आठ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई और घरेलू बजट बुरी तरह बिगड़ गया है। हालांकि, सरकार ने आनन-फानन में बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं और चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। वहीं अब एक रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई गई है कि नींबू-प्याज के बाद अब टमाटर की कीमतों में लगी आग कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी न कर दे। महंगाई से निपटने की केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच टमाटर आ गया है। टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। खुद सरकार भी मानती है कि समस्या तो है, मगर उत्पादक राज्यों से कम आपूर्ति और गर्मी के चलते फसल खराब होने से वह भी कुछ नहीं कर पा रही है।

आधी आबादी को रास्ता चाहिये -भेदभाव नहीं

पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित हुये। यूपीएससी द्वारा चुने गये उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गयी उसके अनुसार श्रुति शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि श्रुति शर्मा के अतिरिक्त तीन अन्य महिला उम्मीदवारों अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंगला तथा ऐश्वर्या वर्मा ने क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। गोया महिला उम्मीदवारों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा की सूची में पुरुषों को सीधे पांचवें स्थान पर धकेल दिया। इनमें कई लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अभावग्रस्त पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद केवल अपनी योग्यता,कठोर परिश्रम व लगन के बल पर इतना ऊँचा मुक़ाम हासिल किया। इस परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अवसर मिले तो महिलायें,क्या कुछ न कर दिखायें। यू पी एस सी की योग्यता सूची में आने वाली इन चारों लड़कियों के अतिरिक्त चुनी गयी सभी लड़कियां उच्च प्रशासनिक पदों पर तैनात होकर राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देंगी। इन्हें इसके बदले में उच्च मानदेय के अतिरिक्त अनेक प्रकार की सुविधाएं गाड़ी बंगला ऑफ़िस नौकर चाकर सब कुछ प्राप्त होगा। पूरे सेवाकाल तक प्राप्त होगा और अवकाशप्राप्ति के बाद भी पेंशन आदि नियमानुसार मिलती रहेगी।

शिक्षण क्षेत्र की प्रतिभाओं से अलग, खेल कूद की अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी विजय पताका फहराकर अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले प्रतिभागियों को सरकारी सेवाओं में अवसर दिये जाने अथवा पेंशन आदि का चूँकि प्रायः कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिये देश का नाम रौशन करने वाले ऐसे होनहारों के लिये केंद्र व राज्य सरकारें अनुकंपा के आधार पर उन्हें पर्याप्त धनराशियां उनके पदक व विजयी श्रेणी के अनुसार आवंटित करती रहती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस तरह के प्रतिभागियों के लिये पदक व श्रेणी के अनुसार अलग अलग धनराशियां निर्धारित भी की हुई हैं। ओलंपिक अथवा विश्व विजेता प्रतिभागियों के लिये तो कई बार सरकारें ख़ुश होकर 'धनवर्षा ' कर देती हैं। उन्हें बांग्ला,प्लॉट करोड़ों रुपयों की प्रोत्साहन राशि यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं तक से नवाज़ा जाता है। ज़ाहिर है इसतरह के प्रोत्साहन से खिलाड़ी प्रतिभागियों के हौसले बुलंद होते हैं,अन्य बच्चे इन्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं और वे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।

परन्तु यह हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्म-जाति की बेड़ियों में जकड़े इस देश का एक बड़ा सांप्रदायिकतावादी व जातिवादी वर्ग खेल कूद प्रतिभागियों के प्रदर्शन को भी उनकी जाति व उनके धर्म के चश्मे से देखता है ? यदि टीम पराजित हो तो यह वर्ग उसका ज़िम्मा अपनी सुविधानुसार जाति या धर्म विशेष पर लगाने की कोशिश करता है और अगर वही खिलाड़ी पदक लेकर आये तो उसको प्रोत्साहित करने के बजाये उसके प्रति उदासीनता बरती जाये ? उसे प्रोत्साहन राशि व अतिरिक्त पुरस्कारों से वंचित रखा जाये ? खिलाड़ियों के साथ इस तरह का सौतेला व पक्षपातपूर्ण बरताव करने के बाद जनता या सरकार यह कैसे उम्मीद कर सकती हे कि देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं में बढ़ोतरी हो ?और भारतीय तिरंगा विश्व फ़लक पर फहराता दिखाई दे ?

याद कीजिये अगस्त 2021 में जब ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना से मैच हार गयी थी उसके कुछ ही देर बाद स्वयं को कथित ऊंची जाति का बताने वाले कुछ तत्व हरिद्वार के एक गांव में रहने वाली भारतीय टीम की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पहुँच कर उसके दरवाज़े के बाहर कपड़े उतार कर नाच नाच कर पटाख़े फोड़ने लगे थे। इतना ही नहीं उन्होंने वंदना कटारिया व उसके परिवार पर जातिगत टिप्पणियां की। उन्हें गालियां दीं व अपमानित किया गया। वंदना के परिजनों के अनुसार आक्रोशित व्यक्तियों का कहना था कि भारत मैच इसलिये हार गया क्योंकि भारतीय टीम में बहुत अधिक दलित खिलाड़ी थे.'इतना ही नहीं बल्कि वे यह भी कह रहे थे कि केवल हॉकी में से ही नहीं बल्कि हर खेल में से दलितों को बाहर निकाल देना चाहिए। ' जिस देश में दलितों को सफलता पाने पर किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन की कोई व्यवस्था न हो वहां किसी हार का ज़िम्मा किसी खिलाड़ी पर केवल इसलिये थोपना कि वह किसी जाति या धर्म विशेष से सम्बद्ध है,यह आख़िर कहाँ का न्याय है ? क्या कभी किसी कथित ऊंची जाति के खिलाड़ी के घर पर भी किसी समाज विशेष के लोगों ने इसलिये प्रदर्शन व हंगामा खड़ा किया कि उसके चलतेअमुक मैच या प्रतियोगिता हार गयी ?

धर्म जाति के आधार पर सौतेले रवैय्ये का ताज़ातरीन उदाहरण पिछले दिनों पुनः देखने को मिला जबकि तुर्की के इस्तांबुल में मुक्केबाज़ी में भारत की निकहत ज़रीन ''विश्व चैंपियन'' बनी। निकहत इसलिये भी अतिरिक्त प्रोत्साहन की हक़दार हैं क्योंकि वह उस मुस्लिम समाज से आती हैं जिसमें कथित तौर पर विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर अधिक तवज्जोह नहीं दी जाती। ख़ासकर खेल कूद प्रतियोगिताओं में तो बिल्कुल नहीं या नाम मात्र। परन्तु यदि ख़ुशक़िस्मती से किसी मुस्लिम लड़की को पारिवारिक सहयोग,समर्थन व प्रोत्साहन मिले तो उसे सानिया मिर्ज़ा और निकहत ज़रीन बनने में देर भी नहीं लगती। हमारी केंद्र सरकार जब तीन तलाक़ पर क़ानून बनाकर इस बात का श्रेय लेना चाहती है कि वह मुस्लिम महिलाओं की शुभचिंतक है। वह बिना किसी पारिवारिक महरम पुरुष के महिलाओं को हज के लिये जाने की इजाज़त देती है। तो उसी मुस्लिम महिला निकहत को विश्व चैंपियन होने व दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने के बावजूद आख़िर अतरिक्त या कम से कम सामान्यतः दी जानी वाली प्रोत्साहन राशि व पुरस्कार,गिफ़्ट आदि क्यों नहीं देती ? उसे क्यों यह कहना पड़ा कि शायद -मैं मुस्लिम थी इसलिए मेरे हिस्से में केवल प्रशंसा आयी।' वंदना कटारिया से लेकर निकहत ज़रीन व इन जैसे और भी कई खिलाड़ियों को आख़िर यह क्यों महसूस होने दिया जाता है कि उनके साथ हो रहे इस सौतेले व्यवहार का कारण यही है कि वे किसी धर्म व जाति विशेष से संबद्ध हैं ? हमारे समाज,सरकार,राष्ट्र प्रेमियों सभी को चाहिये कि वे देश में सद्भावपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण पैदा करें। याद रखें कि रानी लक्ष्मी बाई,रज़िया सुल्तान और बेगम हज़रत महल से लेकर इंदिरा गांधी तक के इस देश में महिला प्रतिभाओं की आज भी कोई कमी नहीं है। बस आधी आबादी को केवल रास्ता व प्रोत्साहन चाहिये -भेदभाव नहीं। (लेखिका - निर्मल रानी/ईएमएस)

मोदी सरकार की आठ साला उपलब्धियों में 'कश्मीरी पंडित' शामिल क्यों नहीं....?

(उपलब्धियों का आईना) अभी-अभी मोदी सरकार ने अपनी आठ साला शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों गिनाई है, इन उपलब्धियों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का तो उल्लेख अवश्य है, किंतु इस क्षेत्र की पिछले तीन दशक से चली आ रही कश्मीरी पंडितों के पुर्नव्यवस्थापन का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि यह धरती के इस 'स्वर्ग' की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या के चलते सेकड़ों हिन्दू कश्मीरी पंडित अपनी जान गंवा चुके है, देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले तीन दशक हर चुनावी घोषणा-पत्र में इस मुद्दें को शामिल किया है, 2014 के चुनावी घोषणा-पत्र में यह मुद्दा शामिल था, किंतु पिछले आठ सालों में इस मुद्दें की सरकार ने पूर्ण रूप से उपेक्षा की, जिसके फलस्वरूप आज 'धरती का यह स्वर्ग' शमशान (नर्क) बनने को मजबूर है, अब तो लाचार व असहाय हिन्दू कश्मीरी पंडितो। को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है, अब सरकार अपनी सफाई में इस वर्ग के कश्मीरियों को सिर्फ इतना आश्वस्त कर रही है कि कश्मीरी पंडितों या हिन्दू कर्मचारियों की तैनाती सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगी, उन्हें ग्रामीण या अन्य असुरक्षित क्षेत्रों में नही रखा जाएगा। सरकार के इस आश्वासन भरे फैसले से तो यही उजागर होता है कि आतंकी हिन्दू कश्मीरियों की हत्याएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही करते है, जब कि अभी तक हुई वारदातों की सूची देखी जाए तो सत्तर प्रतिशत हत्याएं शहरी क्षेत्रों में ही हुई है और उप-राज्यपाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पाक आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों का कुछ भी बिगाड नहीं पाई है, पिछले पांच महीनों में ही तेरह हिन्दूओं की नृशंस हत्याएं की गई है, अब तो ऐसे माहौल से कश्मीरी पंडित इतने डरे सहमें है कि उन्होंने सरकार को 'अल्टीमेटम' दे दिया है कि 'हमे चौबीस घंटे में कश्मीर से शिफ्ट करो, हम कैदियों की जिन्दगी नहीं जीना चाहते, यदि ऐसा नहीं किया गया तो हिन्दू कश्मीरी पंडित सामुहिक पलायन शुरू कर देगें, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी', किंतु सरकार इनकी मांग पर गौर करने के बदले इन पर लाठियां भांज रही है, अब पूरे कश्मीर में करीब तीन दर्जन स्थानों पर सरकार व पंडितों के बीच ऐसी ही जंग छिड़ी हुई है, यहां सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जो हाल ही में आंकड़े जारी किए है उनके अनुसर 1990 से 2020 (तीस सालों में) के बीच आतंकवाद के चलते 65 हजार कश्मीरी पंडितों को अपना मूल निवास स्थान त्याग कर सुरक्षित जगह अपना सिर छिपाना पड़ा है।

अब सरकार तथा केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टीकी मुख्य चिंता यह है कि ऐसे माहौल में जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के चुनाव कैसे करवाए जाएं और वहां केन्द्र का शासन (उप-राज्यपाल की सरकार) कब तक जारी रखा जाए? हाल ही में केन्द्र द्वारा राज्य के करवाए गए गोपनीय सर्वे में भी यही सामने आया है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में माहौल चुनाव के लायक तो कतई नहीं है, जबकि सरकार की चुनाव कराने की संवैधानिक मजबूरी है, भाजपा नेतृत्व की महत्वकांक्षा जम्मू कश्मीर विधानसभा पर कब्जा करने की है इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन आयोग से सीटें बढ़वाने की मशक्कत कराई गई, अब जम्मू में 43 तथा कश्मीर में 47 सीटें हो गई है, कुल मिलाकर 90 सीटों में से बहुमत के लिए भाजपा को कम से कम 46 सीटें चाहिए, राज्य विधानसभा के विगत चुनाव में कश्मीर से भाजपा का मात्र एक सीट मिल पाई थी, जबकि जम्मू की अधिकांश सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, फिर भी भाजपा वहां अल्पमत में ही रही थी, अब भी वही समस्या है, आम कश्मीरी धारा 370 के खात्में का दर्द अभी भुला नहीं पाया है और चूंकि कश्मीर में जम्मू के मुकाबले 4 सीटें अधिक है, इसलिए यहां भाजपा का सपना तो अभी पूरा हो सकता है, जब जम्मू की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा हो और आधा दर्जन सीटें उसे कश्मीर से मिले? और यह असंभव सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहां मोदी विरोध के नाम पर सभी स्थानीय राजनीतिक दल एकजुट हो गए है और सभी ने एकजुट होकर भाजपा के मुकाबले की तैयारी कर रखी है।

इस चुनावी जमा-खर्च के साथ भाजपा की एक बड़ी चिंता यह भी है कि धीरे-धीरे पाकिस्तान का दखल कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों के कारण आम कश्मीरी की सहानुभूति पाकिस्तान के प्रति बढ़ती ही जा रही है, अब आज एक ओर जहां भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को हथियाने के प्रयास कर, आए दिन नई चाले चल रही है वही पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के दिल-दिमाग पर इतना कब्जा कर रखा है कि यदि आज आम जनभावना का सर्वे करवाया जाए तो कश्मीरियों का बहुमत पाक के पक्ष में ही होगा इसलिए कश्मीर को लेकर मोदी सरकार काफी परेशान व दुविधा में है, जिसका हल उसे मिल नहीं पा रहा है। (लेखक- ओमप्रकाश मेहता / ईएमएस)

फलो का राजा आम

हमारे भारत वर्ष में कई प्रकार के फल पाये जाते है जैसे केला, पपीता, तरबूज, अंगूर, सेब, लीची, खरबूजा, आदि लेकिन आम को ही भारतवर्ष में फलों का राजा कहा जाता है भारत सरकार द्वारा आम को राष्ट्रीय फल भी घोषित किया गया है। आम की खेती भारतवर्ष में हजारों वर्ष से हो रही है आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा अन्य फलों की तरह आम की खेती पर भी राष्ट्रीय आम अनुसंधान केन्द्र कई जगह बनाये उसके परिणाम भी अच्छा मिला है कि आज भारतवर्ष में 500 से अधिक प्रजातियों के आम पैदा होते है। भारतवर्ष के कई राज्य आम की खेती के मामले में आगे है। आमों की पैदाबार में उ0प्र0 नं. 1 पर है जहां पर 25 से 25 प्रतिशत आम पैदा होता है। आन्धप्रदेश में 20 प्रतिशत तक आम पैदा होता है। कर्नाटक में 10 प्रतिशत, तेंलगाना में 8 प्रतिशत, बिहार में 9 प्रतिशत छत्तीसगढ़ मे 7 प्रतिशत मध्यप्रदेश के जबलपुर सतना में 2 प्रतिशत आम पैदा होता है।

विश्व के कुल आम उत्पादन 56 प्रतिशत भारतवर्ष में होता है। 24 लाख हैक्टर भारतीय क्षेत्र में आम की फसल होती है। 30 से 40 प्रतिशत दशहरी आम पैदा होता है। कई बार बेमौसम वारिश और आला वृष्टि से आम उत्पादन पर गिरावट आ जाती है।

भारतवर्ष में कई प्रजातियों के आम पाये जाते है। जों निम्न है। - अल्फासों, लगडा, नीलम, मल्लिका, चौसा, अम्रपाली, स्वर्णरेखा, दशहरी, गुलावखास आदि भारतवर्ष आम के पेड़ को पूज्यनीय माना जाता है। आम के पेड़ की व पत्तो की पूजा की जाती है।

आजकल बाजार में विक रहा मीठा रसीला आम आपकी सैहत को बिगाड़ सकता है। बाजार में आने से पहल आम पेड़ो पर नहीं बल्कि गोदाम में कैल्सियम कर्वाईट से पकाये जाते है जो सैहत को काफी नुकसान पहुचातें है। भारत में खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्वाईड से आमों को पकाना प्रतिबधं है। फिर भी मुनाफे के लालच में व्यापारी लोग आम को कैलिसयम कार्वाइड से पकातें है। कार्वाइड़ से आम पकाने की प्रक्रिया के दौरान एसिटिलीन नामक गैस बनती ह। जो शरीर के लिए जहर का काम करती है। ग्ददार देश चीन से चोरी छिपे कई देशों में प्रतिबधं एथलीन राइपनर परवडर से आजकल आमों को पकाया जाता है। एथलीन राइपनर से आम में मौजूद विटामिन ''ए'' के गुण भी खत्म हो जाते है। इस पावडर से पके आम खाने वालों के शरीर में कई गभींर बीमारियों जैसे कैंसर व कीडनी से सम्बन्धित होने की सभावना रहती है।

भारतवर्ष के द्वारा आमों का निर्यात अरब देशो को तथा यूरोपीय में काफी होता हैं पिछले वर्ष यूरोपीय सद्यं द्वारा अल्फासों आम के आयात पर प्रतिबधं लगा दिया गया था इससे भारतवर्ष मे आम निर्माताओं को काफी नुक्सान उठाना पडा था। इस वर्ष उद्योग सगंठनो की पहल कपर युरापीयों सद्यं ने आमों पर से प्रतिबधं हटा दिया गया है।

विदेशों में भारतीयों अल्फासों आम की काफी डिमाण्ड़ है वहां पर यें आम 500 से 600 प्रति किलों के हिसाब से विकता है। कलीम उल्लह खां पदमश्री प्राप्त की है। लखनऊ उ0प्र0के नई सड़क मलिया बाग मे अब्दुला नर्सरी है। कलीम उल्लाह खां द्वारा अपने बाग में एक पेड़ में 300 तरह का अलग-अलग तरह को आम पैदा किया है।उसको स्वंय हमने अपनी आंखो से देखा गया है।

भारतवर्ष के अलावा पाकिस्तान आमों का निर्यात करता है। और पाकिस्तान द्वारा कई देशों उमें भी आम निर्यात किये जाते है। इस वर्ष उ0प्र0 में 44 लाख टल आम उत्पादन होने की संभावना है।

भारतवर्ष इस वर्ष 185 लाख टन आम देश में आम उत्पादन होने की सभावना हैं जबकि पाकिस्तान में 60 हजार टन के आसपास आम पैदा होने की सभांवना है। भारत सरकार द्वारा फलों की खेती तथा अनुसंधान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाईवे बनाने के नाम पर लाखों आम के पेडों को काट दिया गया है हजारों टन फल आम समय पर दूसरे देशों एवं राज्यों में न पहुचनें के कारण सड़ जातें है। इसकी कीमत बागान मालिकों को चुकानी पड़ती है। आज भी कई बागान मालिकों कर्जो में दबे पड़े है। तथा उन्होने आत्म हत्या भी करली है। लेकिन भारत सरकार की खोखली नीतीयों के कारण वह सब विवश है। एक आम को पेड़ 100 साल औसतन आयु होती है। 1250 क्विंटल आम और 60000 की लकड़ी एआम के पेड़ से कमलती है। 25000 टन इजाफा ग्रीन हाउस गैसों से होता है। हर साल होली में 100 किलो आम की लकडी जल जाती है। एक वृक्ष जीवनभर और छाया देता है। और दो टन कार्वन सोखता हैं।

आम ज्यादातर लोगों को पसन्द होता हैं। गर्मी में आने वाला यह ऐंसा फल है। जो लू और इस मौसम से जुड़ी दिक्कतों से राहत देने के साथ पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। कच्चे आम में विटामिन सी ज्यादा रहता है। जितनी कि 35 सेब, 18 केले, 9 नीबू और 3 सतंरे में पाई जाती है। आम में इतने पोषक तत्व पाए जाते है, जिनसे कई सारी बीमारियों में आराम मिल सकता है, साथ ही यह उच्च तापमान के नकारात्मक प्राभावों से भी हमें बचाता है।

आयुर्वेद में भी कच्चे आम की कई खूबीयों के बारे में बताया गया है। कच्चा आम में बिटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। जिससे रक्त विकार को दूर किया जा सकता है। कच्चे आम में काफी मात्रा में फाईबर पाया जाता है। यह खासकर पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे एसिडिटि, पित्त की समस्या दूर करने के साथ वजनन भी नियंत्रित करने में मदद करता है। आम के वृक्ष की कोमल छाल ग्रही और प्रमेह, रक्त विकार, कफ पित एवं प्रण (घाव) का नाशक है आज की जड शीतल आरामदायक रूचि कारक कसेली तथा पित कफ का शमन करती है। आम के पत्ते कीटाणु नाशक खासी आदि विकारो को दूर करने में उत्तम है।

गर्मी के दिनों में आप त्वचा को चमकदार व बेदाग बनाने की इच्छा रखते हो तो आम का सेवन खाने से पहले पानी में धोकर करें। आम बिटामिन ए, बी,एवं सी प्राकृतिक फूड एसिड (नाईट्रिक ऐसिड) और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो चेहरे में निखार लाता है इसके अलावा आम में शरीर को मजबूत रखने वाला कार्बोहाइडेक्रट फाइबर, प्रोटीन, कैल्सियम और आयरन और पोटेशियम समेत अनेक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहतें है। (स्वतंत्र पत्रकार) (लेखक - विष्णु अग्रवाल/ईएमएस)

आज का इतिहास 4 जून

1647 इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम को सेना ने बंधक बना लिया.

1813 प्रसिया और फ्रांस के बीच युद्ध विराम हुआ.

1943 सेना ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति रेमन कैस्टिलों को सत्ता से हटा दिया.

1956 मिश्र ने स्वेज नहर का संचालन करने वाली कंपनी को छूट जारी नही रखने की घोषणा की.

1970 प्रशांत सागर स्थित टोंगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का सदस्य बना.

1991 इसरायली विमानों ने सूडान में फलीस्तीनी छापामारों के ठिकानों पर बमबारी की.

1992 रूस और सोवियत संघ से अलग हुए अन्य गणराज्यों ने हथियारों में कटोती की घोषणा की.

1992 शेयर बाजार के घोटालेबाज हर्षद मेहता तथा बैंक अधिकारी गिरफ्तार.

1997 भारतीय उपग्रह इन्सैट-2 डी.का कोरू (फ्रेन्च, गुयाना) में सफल परीक्षण.

1997 सेंट किट्स कांड में नरसिम्हा राव और के.के. तिवारी को अदालत ने बरी कर दिया.

1999 भारतीय पायलट नचिकेता दिल्ली पहुंचे.

2001 हिंसक व प्रदर्शनों व जनविरोध के बीच ज्ञानेंद्र नेपाल के नये नरेश बने.

शब्द पहेली - 7306

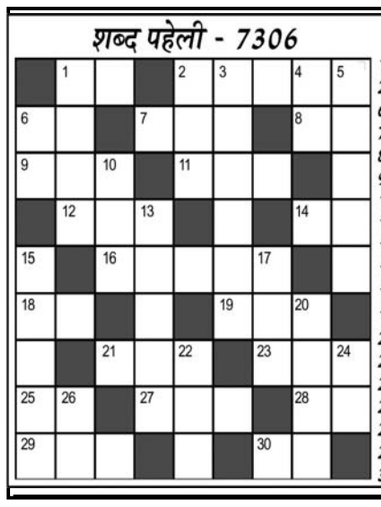

बाएँ से दाएँ

1.आस्तिक,अनुगामी,पूजक-2
2.रख-रखाव-2,3
6.देह, बदन-2
7.कारण-3
8.तपस्या-2
9.बंदूकधारी(अंग्रेजी-3)
11.पति की बहन-3
12.प्रतिज्ञा,वचन-3
14.पिता,डैडी-2
16.मन मोहने वाला-5
18.आनंदित-2
19.लवण,खार-3
21.बख्तरबंद,आवरण-3
23.पासों से भविष्य जानना-3
25.आमिर व काजोल की फिल्म-2
27.मुलायम,कोमल-3
28.उस समय-2
29.भ्रमण,घूमना-3,
30.कोलाहल-2

ऊपर से नीचे

1.खतरनाक-4
2.सनम,बालम-3
3.रहने का तरीका-3,3
4.चावल-2
5.बिजली का कौंधना-5
6.कौवा,काग-2
10.सांभर जैसा खाद्य पदार्थ-3
13.मन को भाने वाला-5
15.सहयात्री-5
17.कटि-3
20.निम्न,न्यूनतम-4
22.उत्कर्ष-3
24.अधर,होठ-2
26.संबोधन-2

शब्द पहेली - 7305 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

04 जून 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	वृष में	मिथुन	06.02 बजे से
चंद्र	तुला में	कर्क	08.16 बजे से
मंगल	मीन में	सिंह	10.32 बजे से
बुध	वृष में	कन्या	12.44 बजे से
गुरु	मीन में	तुला	14.54 बजे से
शुक्र	मेष में	वृश्चिक	17.09 ब.से
शनि	कुंभ में	धनु	19.25 बजे से
राहु	मेष में	मकर	21.30 बजे से
केतु	तुला में	कुंभ	23.17 बजे से
राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक		मीन	00.50 बजे से
		मेष	02.20 बजे से
		वृष	04.00 बजे से

शनिवार 2022 वर्ष का 155 वां दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2079 **शक संवत्** 1944
मास ज्येष्ठ **पक्ष** शुक्ल
तिथि पंचमी 04.53 बजे प्रातः को समाप्त।
नक्षत्र पुष्य 21.55 बजे को समाप्त।
योग ध्रुव 04.19 बजे रात्र को समाप्त।
करण बव 15.50 बजे तदनन्तर बालव 04.53 बजे प्रातः को समाप्त।
चन्द्रायु 04.5 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 22° 24'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1871269
जूलियन दिन 2459734.5
कलियुग संवत् 5123
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2548
हिजरी सन् 1443
महीना जिल्काद
तारीख 04

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
काल	05.55 से	07.23 बजे तक	लाभ	05.37 से	07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से	08.51 बजे तक	उद्वेग	07.10 से	08.42 बजे तक
रोग	08.51 से	10.19 बजे तक	शुभ	08.42 से	10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से	11.46 बजे तक	अमृत	10.14 से	11.47 बजे तक
चर	11.46 से	01.14 बजे तक	चर	11.47 से	01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से	02.42 बजे तक	रोग	01.19 से	02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से	04.10 बजे तक	काल	02.51 से	04.23 बजे तक
काल	04.10 से	05.37 बजे तक	लाभ	04.23 से	05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

रूट अब सचिन , कुक और द्रविड़ के क्लब में शामिल हुए

सात टीमों के खिलाफ एक हजार रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने

लंदन (ईएमएस)। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने यहां मेहमान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले ही दिन एक अहम उपलब्धि हासिल की है। रुट ने 11 रनों की अपने छोटी सी पारी के दौरान ही कीवी टीम के खिलाफ अपने 1000 रन पूरे किये। इसी के साथ ही रूट सात टीमों के खिलाफ एक हजार या इससे अधिक रन बनाने के मामले में दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर , एलिस्टर कुक, और राहुल द्रविड़ की बराबरी पर आ गये हैं।

रूट के अब न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ कुल 1003 रन हो गए हैं।

इस प्रकार वह सात अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 या इससे अधिक टेस्ट रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले कुक, सचिन और द्रविड़ ही इस विशिष्ट क्लब में थे। रूट ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ अपने से एक हजार रन बनाये हैं।

अब वह टेस्ट क्रिकेट में दस हजार रन के आंकड़े को पूरा करना चाहेंगे जिससे वह केवल एक शतक की दूरी पर हैं। रूट सौ रन बनाते ही दस हजारी क्लब में शामिल हो जाएंगे। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले एलिस्टर कुक के बाद इंग्लैंड के दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज होंगे।

नॉर्वे शतरंज : आनंद ने हाओ को हराया

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के विश्वनाथन आनंद का नॉर्वे शतरंज में जीत का सिलसिला जारी है। आनंद ने टूर्नामेंट के क्लासिकल सेक्शन में चीन के वैंग हाओ को हराकर अपना लगातार तीसरा मुकाबला जीता है। इसी के साथ ही वह नंबर एक स्थान पर बने हुए हैं। आनंद ने रेग्युलर क्लासिक मैच 30 मूव्स के साथ ड्रॉ किया और फिर आर्मेगडन (सडन डेथ गेम) में मुकाबला जीत लिया। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव और बुल्गारिया के वेसलिन टोपालव को भी पराजित किया था।

वहीं टूर्नामेंट के दूसरे दौर में खेले गए अन्य मैचों में , वाचिएर-लाग्रेव ने शखरियार मामेदयारोव को हराया जबकि तैमूर रादजाबोव ने नार्वे के आर्यन तारी से बेहतर प्रदर्शन किया। नीदरलैंड के अनीश गिरी और वांग हाओ के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा।

एक-दूसरे के

अब भारत से कुछ शर्तों के साथ निर्यात हो सकेगा गेहूं

- भारत ने गेहूं निर्यात पर 14 मई को लगा दिया था प्रतिबंध

नई दिल्ली (ईएमएस)। बांग्लादेश, फिलीपींस और तंजानिया सहित कुछ देशों को गेहूं निर्यात करने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। कुछ शर्तों के साथ निर्यात की यह अनुमति उन देशों में गेहूं भेजने के लिए दी गई है, जिन्होंने अपनी खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से गेहूं देने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत ने गेहूं निर्यात पर 14 मई को प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि जिन कंपनियों को लेटर आफ क्रेडिट जारी हो चुका है, वो गेहूं निर्यात कर सकेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने रॉयटर्स को भारत से गेहूं निर्यात किए जाने की जानकारी दी है। भारत बांग्लादेश, फिलीपिंस, तंजानिया और मलेशिया को 4,69,202 टन गेहूं भेजेगा। गेहूं व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि लगभग 17 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर पड़ा है। भारत में मानसून सीजन शुरू होने वाला है। मानसून की बारिश से इस गेहूं के खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध के चलते मई में भारत का गेहूं निर्यात घटकर 11.3 लाख टन रह गया, जबकि अप्रैल में यह 14.6 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। गेहूं की वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण, भारत में गेहूं की कीमतों में भी भारी उछाल आया था। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि, विशेष शर्तों के तहत गेहूं के निर्यात को अनुमति देने की बात तब सरकार ने कही थी। ताजा शिपमेंट की अनुमति लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिये दी गई है जो पहले ही जारी किए जा चुके हैं । साथ ही इस गेहूं की आपूर्ति ऐसे देशों को की जानी है, जिन्हें अपनी फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं की जरूरत है । ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स से जुड़े तीन डीलर्स ने बताया कि विभिन्न बंदरगाहों पर कम से कम 17 लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है। इस साल 80 लाख से 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात की अनुमति मिलने की उम्मीद की जा रही थी। पिछले साल 72 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति मिली थी।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन सुबह बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई पर समय के साथ ही बिकवाली हावी होने से बाजार नीचे आने लगा। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स अंतिम क्षणों में बिकवाली हावी होने से 48.88 अंक करीब 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ ही 55,769.23 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 56,432.65 के उच्च स्तर पर जबकि 55,719.36 अंक के निचले स्तर तक गया।

वहीं पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गिरावट के साथ ही 43.70 अंक तकरीबन 0.26 फीसदी नीचे आकर 16,584.30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक में प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा, विप्रो, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लि. लाभ में रहे। वहीं गत दिवस बाजार लाभ के साथ ही बंद हुआ था।

रूस अगले सप्ताह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट करेगा

इंग्लैंड से रूसी प्रायद्वीप के निवासियों को एक विशाल अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की चेतावनी दी गई

मॉस्को (ईएमएस)। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस अपने मिसाइलों की टेस्टिंग भी कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्चिंग का ऐलान किया है। इंग्लैंड से बड़े एक क्षेत्र में मिसाइल की लॉन्चिंग होगी। हालांकि, मिसाइल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड से बड़े रूसी प्रायद्वीप के निवासियों को एक विशाल अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की चेतावनी दी गई है। इसे शायद अगले सप्ताह के शुरुआती तीन दिनों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी मिलाइल और लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन कामचटका क्षेत्र के निवासियों को आगामी हथियारों के परीक्षण को लेकर चेतावनी दी गई है। रूसी सेना ने 20 अप्रैल को इस तरह की एक मिसाइल का परीक्षण किया था. सतान-2 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल को आम बोलचाल में शैतान मिसाइल भी कहा जाता है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। इस मिसाइल पर 10 या इससे अधिक वारहेड्स लगाए जा सकते हैं। कामचटका के अधिकारियों ने आसपास रहने वालों और क्षेत्र में पर्यटकों को चेतावनी जारी की है कि मिसाइल परीक्षण अपेक्षाकृत जल्द होगा । 6 जून से 10 जून के बीच किसी भी दिन लॉन्चिंग हो सकती है। अधिकारियों ने कहा गया ?कि हम लोगों की आवाजाही, सभी प्रकार के उपकरणों, विमानन उड़ानों और पर्यटक समूहों के लिए आगामी लॉन्च और की घोषणा कर रहे हैं। रूस ने 2 जून को अपनी नई हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया है। इसे साल के अंत तक नॉर्थ फ्लीट के वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। रूसी युद्धपोत एडमिरल गोलोवकोस वो पहला वॉरशिप होगा, जिस पर इसे तैनात किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने जिरकॉन को नई पीढ़ी का बेजोड़ आर्म्ड सिस्टम बताया है।

यह मिसाइल साउंड की स्पीड से भी 9 गुना तेज है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पिछले हफ्ते उसने बाट्र्स सी में एक शिप से जिरकॉन क्रूज मिसाइल का व्हाइट सी में करीब 1,000 किमी (625 मील) दूर टारगेट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके अलावा मार्च में किन्झॉल हाइपरसॉनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। किन्झॉल रूसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब खंजर होता है। पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं, क्योंकि 1,500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकती है। इस मिसाइल की टेस्टिंग पहली बार 2018 में की गई थी। किन्झॉल मिसाइल साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है और 3 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है।

सोने का भाव बढ़ा, चांदी भी हुई महंगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। वै?श्विक बाजारों में कीमती धातुओं को समर्थन ?मिलने से एमसीएक्स पर शुक्रवार को सोना अ और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। सोने की कीमत में 0.08 फीसदी की तेजी आई और इसका भाव बढ़कर 51,311 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। वहीं चांदी का भाव 0.58 फीसदी बढ़कर 62,698 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन कीमती धातुओं के दाम में तेजी देखने को मिली है। यहां बता दें ?कि आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है।

मई में सेवा गतिविधियां 11 वर्षों में तेज गति से बढ़ीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां इस साल मई में इसमें पिछले 11 वर्षों की सबसे तेज वृद्धि हुई। एक मासिक सर्वेक्षण में शुक्रवार को बताया गया कि लागत में बढ़ोतरी के बाजवूद नए व्यवयास में वृद्धि के चलते ऐसा हुआ। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल का भारत सेवा पीएमआई व्यवसाय गतिविधि सूचकांक मई में बढ़कर 58.9 हो गया, जो अप्रैल में 57.9 था। अच्छी मांग और नए व्यवसाय में वृद्धि के चलते यह बढ़त हुई। यह लगातार 10वां महीना है, जब सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में विस्तार हुआ। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाता है। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की आर्थिक संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने से सेवा क्षेत्र को समर्थन मिला है। मई में व्यावसायिक गतिविधियां 11 वर्षों में सबसे गति से बढ़ी, जो नए व्यवसाय से समर्थित थीं।

आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों पर कार्रवाई न होना है दुखदःभारत

जेनेवा(ईएमएस)। भारत ने कहा है कि आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों पर कार्रवाई नहीं करना एक दुखद स्थिति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिषद के अध्यक्ष अल्बानिया की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही और न्याय की मजबूती पर खुली बहस के दौरान विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने कहा आतंकवाद आज मानव जाति के लिये सबसे बड़ा खतरा है जो सामाजिक तनाव को बढ़ाता है, समाज को अस्थिरता और हिंसा की ओर धकेलता है।

सिंह ने कहा जब हम जवाबदेही की बात करते हैं, तो यह वास्तव में एक दुखद स्थिति है कि आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, जवाबदेही पर कोई भी बहस आतंकवादी ताकतों द्वारा किए गए नरसंहार को ध्यान में रखे बिना अधूरी होगी, विशेष रूप से वह जो राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के तत्वों द्वारा समर्थित हैं। उन्होंने परिषद में कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद के संकट का सामना कर रहा है और इस वजह से हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं लेकिन वह वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में हमेशा सबसे आगे रहा है।

अमेरिका में फिर खुलेआम फायरिंग, कई घायल

ग्रेसलैंड कब्रिस्तान पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं, पुलिस कर रही है मामले की जांच

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में एक बार फिर खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। गुरुवार को अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में एक अंतिम संस्कार के दौरान एक शूटर ने कई लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रैसीन पुलिस विभाग ने ट्विटर पर बताया कि दोपहर दो बजे के बाद ग्रेसलैंड कब्रिस्तान पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं। कई लोग घायल हैं। हालांकि घायलों की संख्या कितनी है यह अभी स्पष्ट नहीं है और घटनाक्रम जारी है। साथ ही ट्वीट कर यह भी कहा कि मामले की जांच जारी है। पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से घटनास्थल के आसपास जाने से मना भी किया। वहीं स्थानीय मीडिया ने बताया कि अंतिम संस्कार में पांच लोग घायल हो गए थे। गौरतलब है ?कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में लगातार खुलेआम गोलीबारी के मामले सामने आ रहे हैं। ओक्लाहोमा के तुलसा स्थित एक अस्पताल परिसर में युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। साथ ही हमलावर की भी मौत हो गई थी। इससे पूर्व एक स्कूल के बाहर दीक्षांत समारोह के दौरान पार्किंग विवाद में युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कुछ दिन पूर्व ही टेक्सास में एक छात्र ने स्कूल में घुसकर अपने ही स्कूल के छात्रों पर फायरिंग कर दिया, जिसमें 21 मासूम छात्रों की मौत हो गई। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था।

जुलाई के बाद पैन-आधार लिंक करवाने पर करना होगा ज्यादा भुगतान

- 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का भरना होगा जुर्माना

नई दिल्ली (ईएमएस)। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 पहले ही किया जा चुका है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद आधार-पैन लिंक करवाने पर आपको कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। इसकी घोषणा सीबीडीटी ने 29 मार्च 2022 के अपने नोटफिकेशन में कही थी और 30 मार्च 2022 को जारी कर भी इस बात का जिक्र किया गया था। अगर आप अपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि, 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने अपने आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है, वह अपने पैन का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। यानी वजह पैन कार्ड का इस्तेमाल कर के इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और रिफंड को भी प्रोसेस कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर इनकम टैक्स ?नियम 1962 को संशोधित किया है। संशोधन के तहत जो नागरिक 31 मार्च 2022 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराएंगे, उनके पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन यह मौका जुर्माने के साथ मिलेगा।

सीबीडीटी के मुताबिक 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पीएएन) को विशिष्ट पहचान संख्या से नहीं जोड़ने वाले टैक्सपेयर्स को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर इनकन टैक्स रूल्स 1962 में संशोधन किया गया है। यह जुर्माना एक अप्रैल से अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा। 31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का पीएएन निष्क्रिय हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में आप पर आयकर कानून (के सेक्शन 272ँ के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

यूपीआई से लेन-देन 10 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में डिजिटल भुगतान में तेजी देखी जा रही है और इसमें यूपीआई नंबर वन पर चल रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनसीपीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई महीने में यूपीआई से लेनदेन 10 लाख करोड़ रुपए के पार निकलकर 10.41 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। यह अब तक का उच्चतम स्तर है। भारतीय यूनिकॉर्न टिकाऊ और भरोसेमंद रोजगार देने में फिसड्डी, 23 फीसदी स्टार्टअप केवल मुनाफा कमा रहे हैं। एनपीसीआई के आंकड़ों को देखें तो महीने-दर-महीने के आधार पर इस साल मई में लेन-देन की संख्या में सात फीसदी का उछाल आया है, जबकि राशि छह फीसदी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, नकद भुगतान का चलन कमजोर पड़ा है। एनसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआई से 46 अरब लेन-देन हुए जिनकी कुल राशि 84.17 लाख करोड़ रुपये रही। मई 2022 में यूपीआई के जरिए कुल 5.95 अरब लेन-देन किए गए। इससे पहले अप्रैल महीने में 5.58 अरब यूपीआई लेन-देन किए गए थे और लेन-देन की राशि 9.83 लाख करोड़ रुपए रही थी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में लेनदेन की संख्या दोगुने से ज्यादा पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी के काल में लोगों के लिए डिजिटलीकरण बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। यही कारण है कि पिछले दो वर्ष में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है।

अमेरिका में 2022 में गोलीबारी की 233 घटनाएं हुई, बाइडेन ने गन कल्चर बदलने के दिए संकेत

-गन खरीदने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में लगातार पनप रही गन संस्कृति ने आम लोगों की जीना हराम कर दिया है बीते कुछ बरसों में अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाओं की बाढ़-सी आ गई है। इसके लिए देश में बंदूक खरीदने और रखने की आसान शर्तों को जिम्मेदार बताया जाता रहा है। अमेरिका के इस गन कल्चर पर पाबंदियों की मांग लंबे समय से होती रही है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूकबाजी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं। उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस से अपील की है कि वह असॉल्ट गन और उच्च क्षमता वाली मैगजीन की बिक्री पर बैन लगाए। अगर ऐसा करना मुमकिन न हो तो गन खरीदने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए। उन्होंने बंदूक रखने वालों और बनाने वालों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। साथ ही, स्कूली स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ की समस्याओं को दूर करने के लिए काउंसलर नियुक्त करने की भी बात कही।

अमेरिका में अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाओं में पिछले कुछ समय में तेजी से इजाफा हुआ है। एनपीआर डॉट ऑर्ग ने गन वॉयलेंस आर्काइव के हवाले से बताया कि इस साल 2022 में अब तक मास शूटिंग की 233 वारदातें हो चुकी हैं। सबसे ताजा घटना ओक्लाहोमा के तुलसा में बुधवार को हुई। यहां एक युवक ने अस्पताल परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। इससे पहले 24 मई को टेक्सास के एक एलिमेंटरी स्कूल में एक शख्स ने मासूम बच्चों और टीचरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं, जिसमें 19 छोटे बच्चों और 2 टीचरों की मौत हो गई थी। इससे 10 दिन पहले 14 मई को न्यूयॉर्क के बफैलो में एक ग्रॉसरी स्टोर में एक बंदूकधारी ने 10 लोगों की हत्या कर दी थी।

गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं को लेकर गन पॉलिसी में बदलाव की वकालत करने वाले राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार को वाइट हाउस से अपने संबोधन में देश की मौजूदा बंदूक नीति को बदलने का खाका पेश किया। सीएनएन के मुताबिक, उन्होंने 1994 का वह कानून फिर से लागू करने का आह्वान किया, जिसके तहत असॉल्ट वेपन्स पर बैन लगा दिया गया था। इसकी मदद से एक ही दशक में गोलीबारी की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली थी। लेकिन 2004 में रिपब्लिकन के दौर में इसे खत्म कर दिया गया था और लोगों को आसान नियमों पर असॉल्ट बंदूकें मिलने लगी थीं। इसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाएं तिगुनी हो गईं। बाइडेन ने कहा कि अगर कांग्रेस हथियारों को बैन नहीं कर सकती तो उसे कम से कम गन खरीदने की कानूनी उम्र को बढ़ा देना चाहिए। बाइडेन का सुझाव है कि लोगों को 18 साल की उम्र में बंदूक खरीदने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ये उम्र 21 साल की जानी चाहिए। उनका कहना था कि गन लाइसेंस देने से पहले अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए। रेड फ्लैग कानून लागू होना चाहिए। इसके अलावा, गन निर्माताओं को कानूनी जवाबदेही से छूट के नियम को भी खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान में दिए गए ये अधिकार संपूर्ण नहीं हैं। उनका इरादा बंदूक रखने वालों को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन उनमें जिम्मेदारी का अहसास जगाना जरूरी है।

बाइडेन ने मार्मिक अपील करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों का डाटा देखें तो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी और सैनिकों से ज्यादा संख्या ऐसे बंदूकों के हमले में मारे गए स्कूली बच्चों की है। भगवान के लिए जरा इनके बारे में भी सोचिए। हमें और कितने नरसंहार देखना बाकी है। बाइडेन ने कहा कि अब बस बहुत हुआ। अब समय है, कुछ करने का। हम में से हरेक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन बच्चों के लिए, जिन्हें हम खो चुके हैं। उन बच्चों के लिए, जिन्हें हम बचा सकते हैं। और उस देश के लिए, जिससे हम प्यार करते हैं। अब समय आ गया है कि हम आखिरकार कुछ ठोस कदम उठाएं।

स्वदेशी 5जी सेवाएं अगस्त तक हो सकती है शुरूः चौहान

नई दिल्ली (ईएमएस)। दूरसंचार राज्यमंत्री देवु सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार स्वदेश में विकसित 5जी सेवाएं इस साल अगस्त तक शुरू कर सकती है। उन्होंने हाल ही में आयो?जित वर्ल्ड समिट ऑफ इनफॉर्मेशन सोसायटी (डब्ल्यूएसआईएस) 2022 में यह बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र निकाय अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने किया था। यह भी कहा कि सरकार दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिये वित्तपोषण को लेकर शोध एवं विकास कोष शुरू कर रही है। एक बयान में उनके हवाले से कहा गया है ?कि भारत ने एक स्वदेशी 4जी ढांचा विकसित किया है जिसमें 4जी कोर और रेडियो एक्सेस नेटवर्क का डिजाइन और परीक्षण किया गया। यह परिचालकों को किसी भी विक्रेता को चुनने में मदद करता है और लागत में कमी लाता है। स्वदेशी 5जी ढांचे को भी अगस्त, 2022 तक चालू किए जाने की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस और सार्वजनिक क्षेत्र की सी डॉट (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स) 5जी तकनीक विकसित करने में लगी हुई है, जिसे बीएसएनएल नेटवर्क पर तैनात किए जाने की संभावना है।

देश में वस्तुओं का निर्यात मई में 15.46 प्रतिशत बढ़कर 37.29 अरब डॉलर पहुंचा

- आयात बढ़ने से व्यापार घाटे में भी हुई वृद्धि

मुंबई (ईएमएस)। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और टेक्सटाइल क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहने से देश का वस्तुओं का निर्यात मई में 15.46 प्रतिशत बढ़कर 37.29 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि मई 2021 में व्यापार घाटा 6.53 अरब डॉलर रहा था। मई में आयात 56.14 प्रतिशत बढ़कर 60.62 अरब डॉलर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा ?कि देश का वस्तुओं का निर्यात अप्रैल-मई, 2022-23 में 22.26 फीसदी बढ़कर 77.08 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष के पहले दो माह में निर्यात का आंकड़ा 63.05 अरब डॉलर रहा थामई 2022 में पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात 91.6 प्रतिशत उछलकर 18.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान कोयला, कोक और ब्रिकेट्स का आयात बढ़कर 5.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले साल के समान महीने में दो अरब डॉलर रहा था। समीक्षाधीन महीने में सोने का आयात बढ़कर 5.82 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो मई 2021 में 67.7 करोड़ डॉलर रहा था। इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 23.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

पिछले साल मई के महीने में व्यापार घाटा 6.52 अरब डॉलर था। इसका एक कारण यह था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने दूसरे देशों से आयात कम किया था। जारी वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में भारत का निर्यात 22.26 फीसदी बढ़कर 77.08 अरब डॉलर रहा। वहीं. आयात 42.35 फीसदी बड़कर 120.81 अरब डॉलर पहुंच गया। इस साल मई में गैर-पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 44.7 फीसदी बढ़कर 42.48 अरब डॉलर हो गया था। यह पिछले साल मई में 29.36 अरब डॉलर था। वहीं, तेल, गोल्ड, सिल्वर और बहुमूल्य मेटल के अलावा अन्य उत्पादों के आयात में 27.2 फीसदी का उछाल देखने को मिला। बीते महीने इनका आयात 33.61 अरब डॉलर पर रहा।

सब्जियों पर महंगाई की मार, एक साल में दोगुने हो गए दाम

नई दिल्ली (ईएमएस)। महंगाई की मार से सब्जियां भी अछूती नहीं रही पिछले एक साल में जिस तेजी इनके बढ़े हैं, लोगों की खरीदारी भी उसी रफ्तार से कम हो रही है। महंगी सब्जियों की वजह से लोग कम खरीद कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकतर सब्जियों की कीमतें पिछले साल से दोगुनी हो चुकी हैं। सिर्फ टमाटर की बात करें तो दिल्ली में अभी यह 39 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिक रहा है, जबकि एक साल पहले इसकी कीमत 15 रुपये थी। राजधानी को छोड़ दें तो अन्य शहरों में टमाटर कई गुना महंगा हो चुका है। मुंबई में इसकी कीमत 77 रुपये किलो है, जो पिछले साल 28 रुपये के भाव था। कोलकाता में भी पिछले साल 38 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अब 77 रुपये पहुंच चुका है। रांची में भी इसकी कीमत 50 रुपये किलो है, जो पिछले साल तक 20 रुपये के भाव बिक रहा था।

मंडी में ट्रेडर्स से बात करने पर पता चला कि टमाटर की कीमतों में वृद्धि का कारण इसके उत्पादक राज्यों से अन्य जगहों पर सप्लाई घटना है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक टमाटर उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। जहां से इसकी सप्लाई पर बाधाएं आ रही हैं। टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल आलू का भाव 20 रुपये किलो था, जो अब 22 रुपये के भाव बिक रहा है। इसी तरह, मुंबई में पिछले साल तक 21 रुपये किलो बिक रहा आलू अब 27 रुपये में बिक रहा है। कोलकाता में भी पिछले साल के 16 रुपये से बढ़कर आलू 27 रुपये किलो पहुंच गया है। रांची में भी एक साल के भीतर इसकी कीमत 17 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।

अक्सर उपभोक्ताओं के आंसू निकालने वाला प्याज इस बार नरमी बरत रहा है। दिल्ली में प्याज की कीमत पिछले साल के 28 रुपये से गिरकर 24 रुपये पर आ गई है। मुंबई में भी यह 25 रुपये से गिरकर 18 रुपये पर आ गया है, जबकि कोलकाता में 27 रुपये फिसलकर 23 रुपये प्रति किलोग्राम और रांची में 25 रुपये से गिरकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव प्याज बिक रहा है। ये आंकड़े उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंस सविर्सेज के प्रमुख अर्थशास्त्री माध्वी अरोड़ा का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में उछाल आने का सबसे बड़ा कारण महंगा ईंधन है। डीजल के दाम ज्यादा होने की वजह से सब्जियों की ढुलाई पर खासा असर पड़ा है, जिससे इसकी खुदरा कीमतों में उछाल आया। अप्रैल में ऊर्जा क्षेत्र की महंगाई दर 10.80 फीसदी पहुंच गई, जो एक महीने पहले तक 3.5 फीसदी थी। इससे खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी 1.6 फीसदी से छलांग लगाकर 8.4 फीसदी पहुंच गई।

गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में गिरावट का रुखः खाद्य सचिव

नई दिल्ली (ईएमएस)। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि सरकार की तरफ से लिए गए उपायों के बाद गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। सरकार ने बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद चीनी के निर्यात की सीमा को घटाकर प्रति वर्ष एक करोड़ टन कर दिया था। इसके अलावा प्रमुख खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को भी घटा दिया था। कई कदम उठाने के बाद सभी चुनौतियों के बावजूद इनका असर दिख रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि चुनौतियां एक दम से खत्म हो गई है। ये अभी बनी रहेंगी। इन सब चुनौतियों के बावजूद कीमतों में गिरावट का रुख सरकार के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में आटे की औसत खुदरा कीमत 0.30 प्रतिशत घटकर 33.4 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं गेहूं के भाव में भी गिरावट का रुख आया है और इसका भाव एक जून को 29.8 रुपए प्रति किलो है। गेहूं में कीमतों में अब कमी आ रही है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से 19 दिन पहले खुदरा गेहूं की कीमतों में 0.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब, गेहूं के भाव में केवल 0.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का रुख गेहूं और आटे की कीमतों में भी देखा गया है। वहीं चावल को लेकर सचिव ने कहा कि चावल का औसत भाव स्थिर बना हुआ और खुदरा और थोक दोनों बाजारों में इसकी कीमतों में मामूली गिरावट भी देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन और सूरजमुखी के दाम एक साल पहले 35 प्रतिशत बढ़े थे, लेकिन घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ने की वजह से हम इसके प्रभाव से बच सके। उन्होंने कहा कि चीनी का औसत खुदरा दाम 41.50 रुपए प्रति किलो है। पिछले एक माह में चीनी की कीमतों में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की कमी आई है।

स्टेट बैंक के एटीएम से आप उठा सकते हैं कई सेवाओं का फ्री लाभ

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश

पत्नी से विवाद के बाद कांग्रेस नेता भरतसिंह का कुछ समय राजनीति से अलग रहने का ऐलान

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी ने कुछ समय के लिए राजनीति से अलग रहने का ऐलान किया है दो दिन पहले अन्य युवती के साथ पकड़े जाने पर भरतसिंह सोलंकी की पत्नी रेशमा पटेल ने काफी हंगामा किया था इस घटना के बाद आज भरतसिंह सोलंकी ने पत्रकार परिषद में कुछ समय के लिए राजनीति से ब्रेक लेने की घोषणा की उन्होंने कहा कि आगामी 6 महीने तक सक्रिय राजनीति से अलग रहूंगा और उसके बाद कोई फैसला करूंगा हांलाकि उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक कार्य जैसे क्षत्रिय, ठाकोर, ओबीसी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए अब तक जो समय दिया है, उसमें आगामी दिनों में ज्यादा समय दूंगा उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात समेत राज्यभर में घूम घूम कर वहां युवा और संगठनों को एकत्र कर एक मजबूत ताकत के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करूंगा सोलंकी ने कहा कि उनके परिवार को वर्षों से गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज का भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा है, जिसे अब तोड़ने और उन्हें बदनाम करने का यह एक राजनीतिक षडयंत्र है चुनाव से पहले मुझे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अन्य राजनीतिक दल अपनी बढ़त बना सकें कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आते ही महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल, भ्रष्टाचार इत्यादि से लोगों का ध्यान भटकाने की एक राजनीतिक साजिश है मेरे चरित्र के बारे में मुझे कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है मेरे पास सभी प्रमाण हैं, जिसके जरिए मैं स्पष्ट कर सकता हूं लेकिन यह प्रमाण यहां देने की जरूरत नहीं है, इसे मैं कोर्ट के समक्ष पेश करूंगा क्योंकि मामले का निपटारा तो आखिर कोर्ट के जरिए ही होना है सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुआ तब से मेरे 30 साल का सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समेत अन्य किसी प्रकार के विवाद नहीं हुए लेकिन चुनाव निकट आते ही इस मुद्दे को तोड़मरोड कर पेश किया जाता है चुनाव आते ही कभी राम मंदिर के मुद्दे पर तो कभी वायरल वीडियो के जरिए विवाद पैदा किया जाता है मेरा प्रयास था कि घर की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, परंतु बाहर आ गई और इस बारे में मुझे कोई सफाई नहीं देनी जो भी कहना होगा कोर्ट में कहूंगा कुछ दिन पहले राम मंदिर की ईंटों को लेकर दिए बयान के सवाल पर सोलंकी ने कहा कि उसे तोड़ मरोड कर पेश किया गया राम मंदिर निर्माण में सभी की हिस्सेदारी है और उसमें हुए किसी गलत काम पर ऊंगली उठाना मेरा भी अधिकार है मैं हिन्दू धर्म का सच्चा हिमायती और रक्षक हूं लेकिन हरेक बात को राजनीतिक रंग देना का प्रयास किया जा रहा है सोलंकी ने कहा कि मैं ही नहीं देश में ऐसे कई परिवार हैं जिनके वैवाहिक जीवन मुश्किल में है जब मुझे कोरोना हुआ था तब मेरी पत्नी ने मेरे पिता को फोन कर कहा था कि भरतसिंह अब जीवित नहीं रहेंगे जब मैं बिस्तर में पड़ा था और वक्त पत्नी ने पूछा कि मेरा क्या होगा? प्रोपर्टी का क्या? सोलंकी ने कहा कि मैं ऑक्सीजन पर था पत्नी मुझसे प्रोपर्टी मांग रही थी गौरतलब है कि दो दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता भरतसिंह सोलंकी एक युवती के साथ अपने घर में पकड़े गए थे भरतसिंह को युवती के साथ किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी रेशमा पटेल ने पकड़ा था और काफी हंगामा भी किया था चुनाव से पहले विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना कांग्रेस का मुश्किल बढ़ाने वाला था कांग्रेस में ही भरतसिंह के कारण पार्टी की फजीहत होने की चर्चा हो रही थी

विकास योजना में 300 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सके गुजरात के विधायक

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात में 300 करोड़ रूपये से अधिक की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि लैप्स हो जाएगी। वर्तमान विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर यह धनराशि ऐसे ही रह जाएगी।

चुनाव अधिकारों पर शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विधायकों द्वारा संस्तुत 1004 करोड़ रूपये के विकास कार्यों में केवल 677.5 करोड़ रूपये की परियोजनाएं ही 22मार्च तक पूरी हो पायीं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफर्म्स और एनजीओ महिती अधिकारी गुजरात पहल ने निवर्तमान विधानसभा के विधायकों के कामकाज पर यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से तैयार की है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत हर विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1।5 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सिफारिश/सुझाव दे सकता है। जिला योजना बोर्ड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का लेखा-जोखा रखता है। गुजरात में यह योजना 1365 करोड़ रूपये की है। ''

रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायकों द्वारा 2017-22 के दौरान 1004.15 करोड़ रूपये के विकास कार्य संस्तुत किये गये जिनमें से 894.64 करोड़ रूपये जारी किये और उसमें से 677.5 करोड़ रूपये मार्च, 2022 तक खर्च किये गये जो करीब 67.47 फीसद है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''कुल मंजूर की गयी 53,029 परियोजनाओं में से बस 76 फीसद कार्य ही पूरे किये गये। कुल 53,029 मंजूर कार्यों में से केवल 40,428 ही मार्च, 2022 तक पूरे किये गये।''

रिपोर्ट में कहा गया है, ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का आवंटित बजट पांच सालों के लिए था। खर्च नहीं हुई 300 करोड़ रूपये की रकम की अवधि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने जाने के बाद खत्म हो जाएगी। यानी यह रकम प्रभावी ढंग से उपयोग में लायी जा सकती थी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो जाएगा , ऐसे में इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि इतने कम समय में यह बची राशि इस्तेमाल की जा सकती है।

कुपोषण विरोधी लड़ाई के लिए डिजिटल बना गुजरात

- राज्य की 53029 आँगनबाड़ियों से पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन द्वारा 45 लाख लाभार्थियों की निगरानी

अहमदाबाद (ईएमएस) देश के सभी राज्यों में भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया है।इस अभियान के अंतर्गत गुजरात में कुपोषण दर घटाने, गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने, प्रसूति पूर्व सेवाएँ देने, जोखिमकारी लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें संदर्भित सेवाएँ देने और बच्चों के अभिभावकों में कुपोषण के विरुद्ध जागृति लाने जैसी सेवाएँ देने के लिए 'मंगल दिवस' मनाया जाता है। साथ ही अब पोषण ट्रैकर द्वारा सभी ज़िलों की स्थिति की डिजिटली भी समीक्षा की जा रही है।

प्रत्येक आँगनबाड़ी में डिजिटल ट्रैकिंग

पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग 11 रजिस्टर्स के स्थान पर 53029 आँगनबाड़ियों में स्मार्टफोन दिए गए हैं और पूरा कामकाज स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटली किया जाता है। सभी आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन में पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन डाउनलोड की हुई है। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर 99.99ः आँगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं और रजिस्टर्ड अनुमानित 46 लाख लाभार्थियों की देखरेख की जा रही है। विशेष रूप से प्रत्येक आँगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 0से 5वर्ष के बच्चों के विकास व वृद्धि की देखरेख करने के लिए पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों तथा माताओं के लिए ऊँचाई व वज़न मापन संसाधन प्रदान किए गए हैं। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के अनुसार इन संसाधनों के ज़रिये आँगनबाड़ी केन्द्रों पर हाल में अनुमानित 99ः ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाता है।

राज्य भर में कुल 29,91,517 'मंगल दिवस' मनाए गए

किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है और लोगों को पोषण का महत्व समझाने के लिए आँगनबाड़ी स्तर पर जनांदोलन के रूप में 'मंगल दिवस' मनाया जाता है। अब तक पोषण अभियान के अंतर्गत राज्य भर में कुल 29,91,517 'मंगल दिवस' (सीबीई) मनाए गए हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत अगस्त2018 से हर महीने के पहले व तीसरे मंगलवार को ण्ं (ण्दस्स्ल्हूरूं्ं्ं्